ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED

Regd. Office : R-815, (B-11), New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060
Email : alstonetextiles@gmail.com, Website : alstonetextiles.in
CIN : L65929DL1985PLC021037, Tel. : +91-11-28744161, Mob. : +91-9643924382

Date: 03.11.2020

To
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400001

Sub: -Submission of Newspaper Clipping of Advance Notice for the Board Meeting as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Scrip Code-539277)

Dear Sir,

With reference to the above mentioned subject, please find attached herewith the copies of Newspapers- Dainik Mahalakshmi Bhagyodaya (Hindi News Paper) and Money Makers (English Newspaper) dated **03.11.2020** in which the notice of Board Meeting has been published.

You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

For and on behalf of
Alstone Textiles (India) Limited

Ashish Garg
Company Secretary

डीयू के 12 कॉलेजों के टीचर्स को छात्र निधि से वेतन देने पर रोक का आदेश वापस लेने से इनकार

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 02 नवम्बर

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए छात्र निधि के पैसे का इस्तेमाल करने के अरविंद केजरीवाल सरकार के आदेश पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है।

जस्टिस ज्योति सिंह ने दिल्ली सरकार के उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन देने के उसके निर्देश पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था। उन्होंने सरकार से कहा कि पहले हलफनामा दाखिल कीजिए और इसके बाद सभी 12 कॉलेजों का भी पक्ष सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब सरकार ने कहा कि कॉलेजों के पास धन की कोई कमी नहीं है।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के वकील जिवेश तिवारी ने इस मामले में सभी 12 कॉलेजों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कॉलेजों को अगली सुनवाई से पहले जवाब देने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए छात्र निधि के पैसे का इस्तेमाल करने के केजरीवाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने डूसू की ओर से दाखिल याचिका पर आदेश दिया था। दिल्ली सरकार ने उसके द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों को अपने शिक्षकों व कर्मचारियों को छात्र निधि से वेतन देने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने मौखिक तौर कहा था कि छात्रों के कोष को लेने के बजाय, सरकार को कॉलेज के कर्मचारियों को वेतन राशि का भुगतान करना चाहिए। डूसू की ओर से वकील जीवेश तिवारी ने कोर्ट से कहा कि छात्रों से फंड इकट्ठा किया जाता है और सरकार से कुछ नहीं आता है। डूसू ने सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका में कहा है कि छात्र निधि का इस्तेमाल, छात्र कल्याण के अलावा किसी अन्य काम के लिए नहीं किया जा सकता। सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए गया है कि छात्र निधि का इस्तेमाल शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन व भत्ता देने के लिए नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने 16 अक्तूबर को उसके द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों को अपने शिक्षकों व कर्मचारियों का बकाया वेतन, छात्र निधि से देने का निर्देश दिया था। इसके लिए दो सप्ताह के भीतर रकम जारी करने को कहा था। इन कॉलेजों के कर्मचारियों को पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है। डूसू से याचिका में शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन के लिए, छात्र निधि के इस्तेमाल के सरकार के फैसले को मनमाना, गैर कानूनी बताते हुए रद्दकरने की मांग की। डीयू से संबद्ध इन 12 कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है। ये सभी कॉलेज दिल्ली सरकार से 100 फीसदी वित्त पोषित हैं। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, डॉ. भीम राव अम्बेडकर कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, अदिति महाविद्यालय विद्यालय, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हैं।

> जस्टिस ज्योति सिंह ने दिल्ली सरकार के उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन देने के उसके निर्देश पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था। उन्होंने सरकार से कहा कि पहले हलफनामा दाखिल कीजिए और इसके बाद सभी 12 कॉलेजों का भी पक्ष सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब सरकार ने कहा कि कॉलेजों के पास धन की कोई कमी नहीं है।

खाकी वर्दी पहन कोविड-19 नियमों के उल्लंघन में चालान काटने वाला गिरफ्तार

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 02 नवम्बर

दिल्ली की भारत नगर पुलिस ने खाकी वर्दी पहनकर कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने के आरोप में उपेंद्र नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। जांच में मालूम हुआ कि है आरोपी ने सिविल डिफेंस में भर्ती का फॉर्म भरा हुआ था और इसलिए वर्दी सिलाई थी।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात अशोक विहार फेज-4 स्थित एसएफएस फ्लैट के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड नरेंद्र कुमार ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान सफेद रंग की कार से खाकी वर्दी पहने युवक निकला। उसने गार्ड को अपना परिचय सिविल डिफेंस वॉलंटियर उपेंद्र कुमार के तौर पर दिया और कहा कि कार में साहब बैठे हैं जो रात में कोविड-19 से जुड़े उल्लंघन का चालान करने निकले हैं। दर्ज एफआईआर के अनुसार, उपेंद्र सीधे कॉलोनी में घुस गया और बाहर खड़े लोगों के चालान काटकर रुपये जमा करने लगा। इस दौरान उसने 14 से अधिक चालान काटे। रास्ते में एक युवती मिली, जिससे उपेंद्र ने मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान किया। इस बीच सिक्योरिटी गार्ड को कुछ शक हुआ तो उसने उपेंद्र से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वह कार से भाग निकला। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

पीड़ित की शिकायत पर भारत नगर थाने में धोखाधड़ी आदि की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। साथ ही एसएचओ मोहर सिंह मीणा के नेतृत्व में टीम बनाई गई। एसआई आनंद सिंह को युवती से आरोपी उपेंद्र का मोबाइल नंबर मिल गया। फिर इसी नंबर के आधार पर पुलिस ने भलस्वा डेयरी इलाके में छापा मारकर शनिवार को उपेंद्र को गिरफ्तार कर कार बरामद कर ली।

पूछताछ में मालूम हुआ कि वारदात में प्रयुक्त कार उपेंद्र के पिता के नाम पर है जिनकी छह माह पहले मौत हो चुकी थी। आरोपी ने बताया कि उसने सिविल डिफेंस में भर्ती के लिए फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन अभी भर्ती नहीं हुई है। उसने सिविल डिफेंस वालों को चालान काटते हुए देखा तो उसे यह उपाय सूझा। इसके बाद वह अपने दोस्त रमित को अधिकारी बनाकर कार की पिछली सीट पर बैठाता और खुद चालान काटता। पुलिस अब रमित की तलाश में छापेमारी कर रही है। विजिलेंस अधिकारी बनकर एक शख्स ने एसएचओ को फोन कर केस की जांच प्रभावित करने की कोशिश की। जांच में मामला सामने आने पर बवाना थाने में इस बाबत एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार, एक साल पहले बवाना थाने में एक महिला ने पति और ससुराल के लोगों पर दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस अभी जांच कर रही थी। इस बीच तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर धर्मदेव के मोबाइल पर एक शख्स का फोन आया। उसने खुद को बाराखंभा स्थित विजिलेंस विभाग का एसएचओ वीरेंद्र मोर बताया। साथ ही दर्ज एफआईआर की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर धर्मदेव को शक हुआ तो उन्होंने इंस्पेक्टर वीरेंद्र मोर से खुद ही बात की जिससे पता चला कि उन्होंने कोई कॉल नहीं की थी। इसके बाद वीरेंद्र मोर ने अपने विभाग में पहले इसकी शिकायत की। फिर बवाना थाने में भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है।

> अशोक विहार फेज-4 स्थित एसएफएस फ्लैट के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड नरेंद्र कुमार ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान सफेद रंग की कार से खाकी वर्दी पहने युवक निकला। उसने गार्ड को अपना परिचय सिविल डिफेंस वॉलंटियर उपेंद्र कुमार के तौर पर दिया और कहा कि कार में साहब बैठे हैं जो रात में कोविड-19 से जुड़े उल्लंघन का चालान करने निकले हैं।

आप पर निगमों की छवि धूमिल करने का प्रयास : प्रवीण शंकर

नई दिल्ली, 02 नवम्बर

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि गत 4-5 माह से राजनीतिक द्वेष के कारण आम आदमी पार्टी एवं उसके प्रवक्ताओं ने ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री तक भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक संवाद, आरोप-प्रत्यारोप का स्तर आम आदमी पार्टी नेताओं ने इतना गिरा दिया है कि ऐसा लगता है कि हम देश की राजधानी में नहीं किसी दुरदराज खाप पंचायत में राजनीतिक पैतरेबाजी कर रहे हों। यह एक बेहद दुखद स्थिति है, दिल्ली की जनता इसे बहुत गम्भीरता से देख रही है और आम आदमी पार्टी को अपने इन अनर्गल बयानों की आगामी नगर निगम चुनावों में भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2007 से लगातार नगर निगम में सेवारत है और इस अवधि में लगातार कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। इन 13 वर्षों में जनता ने हमें दो बार पुनः चुना है जो नगर निगम में हमारी अच्छी सेवा का प्रमाण है। इस अवधि में कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित नगर निगमों को असफल करने के लिये फंड रोकने का ओछा हथकंडा अनेक बार अपनाया है और आज भी अपनाया हुआ है। चालू वित्त वर्ष आधा हो चुका है पर इस वर्ष का एक तिहाई फंड भी नगर निगमों को नहीं मिला है। एक ओर तो दिल्ली सरकार के द्वारा फंड रोक नगर निगमों को आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा रहा है वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आधारहीन आर्थिक घोटालों के अनर्गल आरोप लगा कर नगर निगमों एवं उनको प्रशासित कर रहे भाजपा नेताओं की छवि धूमिल करने का निरंतर अभियान चला रही है। इस नकारात्मक अभियान के प्रमुख सूत्रधार हैं आम आदमी पार्टी नेता विधायक सौरभ भारद्वाज एवं नेता दुर्गेश पाठक जो निरंतर झूठे, तथ्यहीन, भ्रामक आरोप लगाते हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि इसी भ्रामक अभियान क्रम में आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने कल उत्तरी दिल्ली नगर निगम के भाजपा नेतृत्व पर एक अनर्गल आरोप लगाते हुए प्रति वर्ष 1400 करोड़ के सम्पत्ति कर राजस्व के गबन का दोष लगाया है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। -bjpdelhinew@gmail.com

दो वाहनों को एक ही नम्बर परिवहन कार्यालय में लापरवाही या भ्रष्टाचार

नई दिल्ली, 02 नवम्बर

दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार ने कहा कि गत दिनों दिल्ली में एक ही वी.आई.पी. फैंसी नम्बर प्लेट वाली दो गाड़ियों के होने का मामला ट्रैफिक पुलिस के चालान के बाद सामने आया है जो दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार और लापरवाही की ओर तो इंगित करता ही है पर साथ ही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरे में डालता है।

नवीन कुमार ने कहा है की ऐसे भी समाचार सामने आए हैं जहां परिवहन विभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों ने एक ही नंबर दो-दो वाहनों को दे दिया है और अब अधिकारी निजी स्तर पर यह नंबर वापस करवाने में लगे हैं। यह एक गम्भीर मामला है जो दिल्ली के परिवहन मंत्री के कार्यालय में भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है और इसकी जांच आवश्यक है। दिल्ली भाजपा मांग करती है कि दो वाहनों को एक ही नंबर दिए जाने की उच्च स्तरीय सतर्कता जांच हो और ऐसे सभी पंजीकरण रद्द कर इस मामले के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो।

-bjpdelhinew@gmail.com

बवाना अग्निकांड

आरोपी मनोज जैन एक बार फिर पटाखा फैक्ट्री चलाते हुए गिरफ्तार

नई दिल्ली, 01 नवम्बर (इ.स.)

दिल्ली के बवाना अग्निकांड के मुख्य आरोपी मनोज जैन को एक बार फिर अवैध पटाखों की फैक्ट्री चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, इस बार वह हरियाणा के कुंडली में अवैध पटाखों की फैक्ट्री चला रहा था। छोटे-छोटे बच्चे इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इससे पहले जनवरी 2018 में बवाना में वह अवैध पटाखों की फैक्ट्री चला रहा था, जहां अचानक लगी आग में 17 लोगों की मौत हो गई थी। बहरहाल, वह जमानत पर बाहर था।

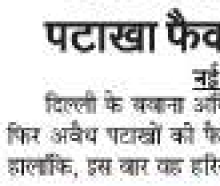

पीड़ित पक्ष के वकील प्रदीप खत्री इस आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए रोहिणी कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। वकील खत्री ने बताया कि आरोपी मनोज जैन को रविवार को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। रोहिणी कोर्ट से वह सशर्त जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन उसने एक बार फिर लोगों की जान से खेलने का प्रयास किया है। वह इस बार अदालत से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जमानत पर बाहर आने के बाद मनोज जैन ने अपनी इसी काली करतूत को जारी रखा। बस इस बार ठिकाना बदल लिया। इस बार उसने पटाखे बनाने के लिए हरियाणा के कुंडली को चुना। वहीं, बवाना अग्निकांड में अपनों की जान गंवा चुके पीड़ित परिवारों का कहना है कि आरोपी मनोज जैन के बहुत रसूख वालों लोगों के साथ संबंध हैं। इसलिए उसने इतनी हिमाकत दिखाई कि दिल्ली में 17 लोगों की मौत के जिम्मेदार ने बेधड़क दूसरी जगह पटाखों की एक बड़ी फैक्ट्री खोल ली। इस फैक्ट्री में छोटे-छोटे बच्चे व महिलाएं काम करती हुई पाई गई हैं। दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों ने पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं अपनी 20 वर्षीय बहन को इस हादसे खो चुके हरचरण का आरोप है कि पुलिस की शह पर ही उसने दोबारा यह कृत्य किया है।

दिल्ली दंगे मामला

कोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार

नई दिल्ली, 01 नवम्बर (इ.स.)

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के साम्प्रदायिक दंगों के मामले में अदालत ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन दंगों का शिकार बने एक व्यक्ति ने अदालत में शिकायतपत्र दाखिल कर कहा था कि उसकी दुकान व मकान लूटा गया था। उसी दौरान उसने देखा था कि भीड़ ने बुर्के वाली एक महिला की हत्या कर उसका शव भागीरथी विहार नाले में फेंक दिया था। हालांकि, पुलिस की तरफ से कहा गया था कि यह आरोप बेबुनियाद है। कड़कड़डूमा स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राकेश कुमार की अदालत ने सोमवार को इस मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि बगैर जांच यह आरोपों को गलत कैसे बता सकते हैं। इस मामले का शिकायतकर्ता खुद दंगों का पीड़ित है। ऐसे में किसी अज्ञात महिला की हत्या कर उसके शव को नाले में डालने की बात को बिना तफ्तीश झुठलाया कैसे जा सकता है। पुलिस को पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए। अदालत ने कानूनी प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी संज्ञानीय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को पहले एफआईआर दर्ज करने एवं उसके बाद मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का नियम है। अदालत में दायर शिकायतपत्र में शिकायतकर्ता ने कहा है कि यह घटना 24 फरवरी 2020 की है। भागीरथी विहार पुलिया के पास ही उसका घर व दुकान है। एक समुदाय विशेष के लोगों ने उसके घर व दुकान पर हमला बोल दिया था। उसकी दुकान लूट ली और फिर दुकान में आग लगा दी। उसके घर में बेटी की शादी के लिए जुटाए गए सामान, नकदी व जेवरात को लूट लिया गया। हालांकि, इस बीच उसने खुद को अपने परिवार को एक अलग कमरे में बंद कर लिया था, जिससे वह बच गया, लेकिन इस घटना से पहले उसने देखा था कि इन दंगाइयों की भीड़ ने एक अज्ञात बुर्के वाली महिला को बुरी तरह घायल कर दिया।

दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हुई

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 02 नवम्बर

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है, लेकिन विपक्षी दल इसे मान नहीं रहे।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (सफर) के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी रविवार को बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है, जो कि इस मौसम का अधिकतम है। इससे पहले शनिवार को प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी 32 प्रतिशत, शुक्रवार को 19 प्रतिशत और गुरुवार को 36 प्रतिशत थी।

गोपाल राय ने पत्रकारों से कहा कि हम बार-बार कह रहे हैं कि दिल्ली में दिवाली के आसपास प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के लिए पराली जलाना एक प्रमुख कारण है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण के पराली जलाने की हिस्सेदारी चार से छह प्रतिशत है, जबकि आंकड़ों के अनुसार यह 40 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जैव अपशिष्ट जलाने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण और धूल प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। 'सफर' के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल एक नवम्बर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि पंजाब और हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में पराली जल रही है। गोपाल राय ने कहा कि नए आयोगों के गठन से अधिक जरूरी जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई करना है। केन्द्र ने हाल ही में एक अध्यादेश के माध्यम से एक नया कानून पेश किया था, जो वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली आयोग का गठन करता है।

मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटिड
CIN: L74899DL1994PLC057941
पंजीकृत कार्यालय : 18/14, डब्ल्यू.ई.ए. पूसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फ़ोन : +91-011-41450121
ई-मेल moongipas@gmail.com वेबसाइट : www.moongipa.net
सूचना
सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 10 नवंबर 2020 को होगी, जिसमें कम्पनी के 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के स्वतंत्र अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर स्वीकृत किया जाएगा।
निवेशक इस संबंध में और विवरण के लिये कम्पनी की वेबसाइट www.moongipa.net और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
कृते मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटिड
हस्ता/-
संजीव जैन
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
दिनांक : 02 नवंबर 2020
स्थान : दिल्ली

मूंगिप्पा कैपिटल फाइनेंस लिमिटिड
CIN: L65993DL1987PLC028669
पंजीकृत कार्यालय : 18/14, डब्ल्यू.ई.ए. पूसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फ़ोन : 011-41450121
ई-मेल moongipac@gmail.com वेबसाइट : www.mongipa.com
सूचना
सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 10 नवंबर 2020 को होगी, जिसमें कम्पनी के 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के स्वतंत्र अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर स्वीकृत किया जाएगा।
निवेशक इस संबंध में और विवरण के लिये कम्पनी की वेबसाइट www.mongipa.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
कृते मूंगिप्पा कैपिटल फाइनेंस लिमिटिड
हस्ता/-
गुलशन आहूजा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
दिनांक : 02 नवंबर 2020
स्थान : दिल्ली

CAPITAL FINVEST LIMITED
Regd. Office: 1002, Arunachal, 19 Barakhamba Road, New Delhi-110001
Phone: 23718585, 23315058,
Website: www.capfin.in,
Email: capital50@yahoo.com
CIN: L67120DL1983PLC016575
NOTICE
Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 11th November, 2020 to approve the unaudited financial results of the Company for the second quarter and half year ended 30th September, 2020.
Further, this information is also available on the website of the Company i.e. www.capfin.in and on the website of the stock exchange, www.msei.in
For Capital Finvest Limited
Sd/-
RATTAN SINGHANIA
(Whole Time Director)
DIN : 00147685
Date: 02.11.2020
Place: New Delhi

SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED
[illegible]
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th November 2020 at 02:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th September 2020 and to consider any other business, if any.
Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct" to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f 30.09.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.
The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.shriniwasleasingfinance.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com.
By order of the Board
For Shri Niwas Leasing And Finance Ltd
Sd/-
Ravi Kumar Dhakar
Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 02.11.2020

SITAL LEASING AND FINANCE LIMITED
[illegible]
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 at 12:00 P.M. at the corporate office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.
Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f 30.09.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.
The information contained in this notice is also available on the Company's website www.sitalleasingfinance.com and also on the website of MSEI limited www.msei.in.
By order of the Board
For Sital Leasing And Finance Limited
Sd/-
Nisha Jain
Company Secretary & Compliance Officer
Place: Gurugram
Date: 02.11.2020

SUNSHINE CAPITAL LIMITED
[illegible]
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th November, 2020 at 04:00 P.M. at the Registered Office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th September 2020 and to consider any other business, if any.
Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct" to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f 30.09.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.
The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.sunshinecapital.in and also on the website of BSE Ltd. i.e www.bseindia.com.
By order of the Board
For Sunshine Capital Limited
Sd/-
Sakshi Gaur
Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 02.11.2020

ABHIJIT TRADING CO LTD
[illegible]
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 at 03:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.
Further, the Company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct" to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f 30.09.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.
The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.abhijittrading.in and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com.
By order of the Board
For Abhijit Trading Co Ltd
Sd/-
Akshay Khare
Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 02.11.2020

ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED
[illegible]
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 at 05:30 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.
Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct" to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.09.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.
The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.alstonetextiles.in and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com.
By order of the Board
For Alstone Textiles (India) Limited
Sd/-
Ashish Garg
Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 02.11.2020

GENESIS DEVELOPERS AND HOLDINGS LIMITED
[illegible]
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the notice is hereby given that, the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 at 03:30 P.M. at the registered office of the Company to, inter-alia, consider and approve the unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business with the permission of the Chairman, if any.
Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.09.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.
The information contained in this notice is also available on the Company's website www.genesisdevelopersholdings.com and also on the website of MSEI Ltd www.msei.in.
By order of the Board
For Genesis Developers And Holdings Ltd
Sd/-
Shikha
Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 02.11.2020

HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED
[illegible]
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th November, 2020 at 12:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.
Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30.09.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.
The information contained in this notice is also available on the Company's website www.hillridgeinvestments.in and also on the website of MSEI Ltd www.msei.in.
By order of the Board
For Hillridge Investments Limited
Sd/-
Sumit Sah
Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 02.11.2020

Hotels and guest house owners worried about fire clearance

MM BUREAU
New Delhi/November 02

Two months after they were allowed to reopen their businesses, owners of hotels and guest houses in the national capital are a worried lot. While their businesses were already badly hit due to the Covid-19 pandemic, a lack of clarity about new fire safety norms, notified by the Delhi government in May last year, have compounded their concerns.

The Delhi Hotel and Restaurant Owners Association (DHROA) met state urban development Satyendar Jain last month to request him to extend by a year the deadline for the implementation of the new norms that are currently under review. The existing deadline was March 31, 2020.

The Delhi government had notified the new fire safety norms in May, three months after a fire in Karol Bagh's Arpit Palace hotel claimed 17 lives.

But following objections raised by hotel and guest house owners, the Delhi government had in November last year constituted a sub-committee chaired by a special commissioner of police (licensing) to review and make appropriate recommendations for fire safety in these institutions. The owners were given time till March 31 this year to comply with the new norms.

Mohit Shah, general secretary, DHROA, said, "There is no clarity on what the status of the new fire safety norms is. We are in a Catch-22 situation. Our establishments have clearance from the fire department as per the old norms. We don't know if we should carry out changes as per the new norms or not, as there is no clarity about the new norms. We want the deadline to be extended till March 31, 2021 so that we can run our businesses without any fear."

However, this committee is yet to submit its report, a senior government official said. A senior Delhi Police officer with the licensing department said, "The report is almost final and is expected to be submitted in the coming week."

When contacted, Jain said, "We will extend the time for compliance due to the Covid-19 situation."

Hotel owners said they want the deadline to be extended at the earliest.

Murli Mani, owner of a hotel in Karol Bagh and DHROA chairman, said, "The business is badly hit due to Covid. We are operating the business in fear due to a lack of clarity about the fire norms. In case there is a fire incident, will the existing fire NOC [no-objection certificate] be considered valid? The fire department is also not renewing expired NOCs. What will happen to those people?"

A senior Delhi Fire Services (DFS) official, who asked not to be named, said, "Those who have not complied with the changes notified in May 2019, do not technically have a valid NOC. As the deadline for implementation has not been extended and the amendment to the new rules not notified, the rules that were notified in May are in force."

As per the new amendments, kitchen or cooking activity in any form is not allowed on rooftops or basements of buildings, and storage of inflammable materials or temporary roofing is banned in terraces.

Besides, inflammable materials — like carpets and wooden or foam panellings — are not allowed on passages, corridors and staircases of buildings, and storage of gas cylinders in violation of standards prescribed by the National Building Code is also banned.

The hotel owners had raised objections to a few provisions in the amendment, such as installation of Carbon monoxide detectors and fire check or protection doors, and no fire NoCs to hotels with more than four floors. "We had objected to installation of fire check doors in guesthouses and suggested that sprinklers be allowed. There were other issues which we had raised. We want our fire NOC to be considered valid till next year. The government should notify the new norms at the earliest," said Boddy Lohia, president of Mahipalpur hotel owners' association.

Former DFS chief AK Sharma said that the government should notify the new norms so that hotel owners can comply with it. "The government should take cognisance and extend the deadline for implementation. Now that the deadline for implementation has not been extended so far, the new rules notified in May are currently in force. But hotel owners can't be held responsible as the government.

Delhi Govt lists over 800 open spaces for residents to burn crackers during Diwali

MM BUREAU
New Delhi/November 02

The Delhi government has published a list of over 800 open spaces across the city where people will be permitted to burn "green" firecrackers between 8pm and 10pm on Diwali.

The list comes even as the Delhi government is scheduled to launch a campaign on Tuesday urging people not to burn fire crackers this Diwali in light of air pollution, which is a greater concern this year owing to the present Covid-19 crisis.

Diwali this year will be celebrated on November 14.

Delhi environment minister Gopal Rai, in line with a 2018 Supreme Court order, said the government has allowed the manufacture and sale of only green crackers, which contain fewer polluting substances as compared to traditional ones,

and are less noisy as well.

In 2018 and 2019, despite the ban on the sale of traditional crackers and due to the low availability of low-emission varieties, pollution levels in the city saw a major spike after Diwali. Till last year, green varieties of only 'phuljhari' (sparklers), rocket and 'anar'(flower pots) were available. More options are available in markets this year.

Rai also said, "I appeal to people to not burn any fire crackers at all this year. Because of the ongoing Covid-19 pandemic, health hazards due to air pollution could turn more dangerous. If anyone really wants to burn firecrackers, then please use only green crackers."

The list of 824 locations, published on the Delhi government's website, includes parks, vacant plots, school playgrounds and open grounds covering all of the city's 272 municipal wards.

Some of the prominent locations include Buddha Park in Mayur Vihar, a park in B block of Chanakyapuri, Ramleela ground in Laxmibai Nagar, Ajmal Khan Park in Karol Bagh, Sudarshan Park in Moti Nagar, West Mehram Nagar Park in Delhi Cantonment, CBD ground opposite Hotel Leela and Gandhi Park in Saket.

A senior government official said the list was released to ensure that even if people choose to burn green firecrackers, they do it in common locations that are more open, instead of streets, lanes and parking areas in residential areas.

Local police and administration officials are also likely to set a cap on the size of gatherings in each open space. Enforcement teams will also remain active during Diwali, a senior official in the government's revenue department said.

BS Vohra, president of East Delhi resident welfare associations' front, said: "We shall be asking members to celebrate Diwali without firecrackers this year. We have already started campaigns through social media platforms. The initiative on part of the government to identify locations for community celebrations reflect good intent, but it can't be said how much it can actually persuade people. We need better awareness campaigns and stricter enforcement of existing norms."

A total of 260 applications for firecracker shop licences have been received so far by Delhi Police, which issued 138 licences till Thursday -- a number much higher compared to 2019 when only 97 had applied of which 62 had received permission to sell firecrackers. Eligible shopkeepers can start selling from Monday.

Anumita Raychowdhury, executive director at the Centre for Science and Environment, said: "The government has to invest in an intensive campaign this year to encourage people not to burn firecrackers. The air pollution problem and spike in covid-19 cases together can create a health disaster. With issuing a list of designated locations for burning firecrackers and setting a time window, the government is apparently trying to ensure that residential areas witness less pollution because of firecrackers during Diwali. But, with that, the government should also make firecracker sales' licensing norms more stringent in order to curb accessibility to firecrackers."

AAP calls North MCD 'corrupt', demands CAG probe; BJP says allegation 'baseless'

MM BUREAU/New Delhi/November 02

The Aam Aadmi Party (AAP) on Sunday accused the Bharatiya Janata Party (BJP)-led North Delhi Municipal Corporation of corruption, and said the civic body has been under-recording the amount of property tax it has collected every year, and demanded the Comptroller and Auditor General (CAG) investigate the matter. The BJP, which governs the three municipal corporations in the city, hit back, calling the allegations "baseless".

"The North MCD should be collecting ₹2,100 crore as property tax from 12 lakh people every year, but records show that only ₹700 crores is collected annually from four lakh people. The remaining ₹1400 crore is siphoned off," said Durgesh Pathak, AAP's in charge of municipal corporation affairs.

He also said, "The BJP leaders are looting ₹1400 crores collected by the MCD in the name of property tax, due to which they cannot pay their employees — doctors, nursing staff, teachers and sanitation workers. AAP demands that this matter should be thoroughly investigated by the CAG." BJP's Delhi unit spokesperson Praveen Shankar Kapoor said, "AAP is a bunch of people who are experts on baseless statements. The party is in power in the Delhi government, and if they feel there is any kind of scam in MCDs they are free to recommend a CBI (Central Bureau of Investigation) probe, or else they should stop churning baseless allegations."

Delhi Police sub-inspector kills himself with service pistol

MM BUREAU
New Delhi/November 02

A sub-inspector (S-I) of Delhi Police allegedly killed himself with his service pistol at his residence in Outer Delhi's Mohan Garden near Ranhola early in the morning on Monday. Police officers said they have learnt that the 26-year-old S-I,

who was posted at a police station in outer district, killed himself due to some financial trouble. A Koan, deputy commissioner of police (DCP), (outer), Delhi Police, said that the Ranhola police station authorities received a call at 5.15 am regarding death by suicide by a man at his home. The caller was the brother of the deceased. A police team reached his home and found that the deceased was an S-I of Delhi Police. "The S-I took the extreme step in a room on the ground floor of his house. His body was on the bed. He used his service pistol," said a police official, requesting anonymity. DCP Koan said that the S-I had worked on Sunday. "We have learnt that he killed himself over some financial trouble. Further investigation is in progress," he said. The police are probing how the S-I managed to bring his service pistol home after his work got over on Sunday. It is being investigated whether the in-charge of the malkhana – a store room in a police station where arms and ammunition are kept – of the police station where the S-I was posted was aware that deceased did not return his service weapon after his duty got over, the officer added.

North-east Delhi riots

HC sets aside trial court's order granting bail to private school principal

MM BUREAU
New Delhi/November 02

The Delhi high court on Monday set aside a trial court order granting bail to Rajdhani School principal Faisal Farooq, an accused in the north-east Delhi riots, while stating that "the entire country is aggrieved by the action of such offenders who tarnish the basic secular fabric of the nation and needs to be punished severely".

Cancelling the bail granted to Farooq on June 20 by additional sessions Judge Vinod Yada, Justice Suresh Kait said that the lower court had failed to appreciate that while deciding an application for bail, the society's interest is also to be safeguarded. He said that "personal liberty of an individual, though precious, is of little value if the larger interest of the people and nation are at

stake."

The Delhi police had challenged the bail granted to Farooq who had been charged for hatching a conspiracy to precipitate and aggravate riots, in and around his school. According to the police, it was on his directions that the adjacent convent school, two parking lots run by the other party and the building of one Anil Sweets were destroyed by the mob.

The police claimed in the charge sheet that the call detail analysis of Farooq suggested that the he had links with prominent members of Popular Front of India, Pinjra Tod group, Jamia Coordination Committee, and other persons, which indicate the depth of the conspiracy.

While cancelling Farooq's bail, the judge said, "The accused has been charged with criminal conspiracy. His absence from the spot does not absolve him of his liability in this case."

In their charge sheet, the police had claimed that the rioters had camped inside and fired bullets from the terrace of Rajdhani School. They also threw petrol bombs, acid, bricks, stones and other missiles using an improvised large iron catapult, specially installed for the purpose, from the terrace. Police also said that on February 24, the day of the riots, many children had been told to leave the school early, along with their parents, during the half time.

'Baba Ka Dhaba' owner accuses YouTuber of misappropriation of funds

MM BUREAU/New Delhi/November 02

Kanta Prasad, the owner of popular eatery 'Baba Ka Dhaba' in south Delhi's Malviya Nagar, has filed a complaint against Instagram influencer Gaurav Wasan for misappropriation of funds, police said on Sunday. Prasad (80) had shot to fame after a video of him tearfully recounting the desperation of the months since the lockdown was

shared widely across social media platforms recently. Ironically, Prasad's despair had come to light when Wasan captured the eatery owner breaking down as he talked about his struggles in a video shared on the YouTuber's social media account. In his complaint to police, Prasad said Wasan shot his video and posted it online and convinced the public on social media to donate money to the eatery onwer. He further alleged that Wasan "intentionally and deliberately shared only his and his family/friends bank details and mobile numbers with the donors and collected huge amount of donation through different mode of payments i.e bank account/wallets without providing any information to the complainant". The owner of the food joint also accused the YouTuber .

Delhi Govt mulls ban on sale of loose cigarettes, beedis

MM BUREAU
New Delhi/November 02

The Delhi government is mulling to ban the sale of loose cigarettes and beedis to discourage people from consuming such items as they are injurious to health.

A senior government official said on condition of anonymity that the Maharashtra government had imposed a similar ban in September last year. "This matter is still being discussed and is at a very initial stage at the moment. Legally, it is possible. The rule laid down by the central government states that no person can trade or do commerce in cigarettes or any other tobacco product, unless when such product is sold, supplied or distributed by him/her, it bears thereon on its label the specified health warning," said the official. The ban can be imposed under sub-section 2 of section 7 of the cigarettes and other tobacco products (prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production.

MOONGIPA SECURITIES LIMITED
CIN : L74899DL1994PLC057941
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi -110005. Tel: +91-011-41450121
Email : moongipas@gmail.com Website: www.moongipa.net

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 10, 2020, inter alia, to consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020.

Investor may visit the Websites of the Company www.moongipa.net and the Stock exchange www.bseindia.com for further details in this regard.

For MOONGIPA SECURITIES LIMITED
Sd/-
Sanjeev Jain
Company Secretary & Compliance Officer
Date : November 02, 2020
Place : Delhi

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED
CIN : L65993DL1987PLC028669
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi -110005. Ph.: 011-41450121
Email : moongipac@gmail.com Website : www.mongipa.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 10, 2020, inter alia, to consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020.

Investor may visit the Websites of the Company www.mongipa.com and the Stock exchange www.bseindia.com for further details in this regard.

For MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED
Sd/-
Gulshan Ahuja
Company Secretary & Compliance Officer
Date : November 02, 2020
Place : Delhi

CAPITAL FINVEST LIMITED
Regd. Office: 1002, Arunachal, 19 Barakhamba Road, New Delhi-110001
Phone: 23718585, 23318050,
Website: www.capfin.in,
Email: capital93@yahoo.com
CIN: L67120DL1983PLC016575

NOTICE

Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 11th November, 2020 to approve the unaudited financial results of the Company for the second quarter and half year ended 30th September, 2020.

Further, this information is also available on the website of the Company i.e. www.capfin.in and on the website of the stock exchange, www.msei.in

For Capital Finvest Limited
Sd/-
RATTAN SINGHANIA
(Whole Time Director)
DIN : 00147685
Date: 02.11.2020
Place: New Delhi

SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED
[illegible]

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th November 2020 at 02:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th September 2020 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct" to Regulate, Monitor & Report Trading by insiders w.e.f 30.09.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.shriniwasleasingfinance.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com.

By order of the Board
For Shri Niwas Leasing And Finance Ltd
Sd/-
Ravi Kumar Dhakar
Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 02.11.2020

SITAL LEASING AND FINANCE LIMITED
[illegible]

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 at 12:00 P.M. at the corporate office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by insiders w.e.f 30.09.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.sitalleasingfinance.com and also on the website of MSEI limited www.msei.in.

By order of the Board
For Sital Leasing And Finance Limited
Sd/-
Mahu Jain
Company Secretary & Compliance Officer
Place: Gurugram
Date: 02.11.2020

SUNSHINE CAPITAL LIMITED
[illegible]

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th November, 2020 at 04:00 P.M. at the Registered Office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th September 2020 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct" to Regulate, Monitor & Report Trading by insiders w.e.f 30.09.2020 till the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website i.e. www.sunshinecapital.in and also on the website of BSE Ltd. i.e www.bseindia.com.

By order of the Board
For Sunshine Capital Limited
Sd/-
Sakshi Gaur
Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 02.11.2020

ABHIJIT TRADING CO LTD
[illegible]

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 at 02:00 PM at the Regd. Office of the Company, inter alia, to [illegible]

[illegible]

Place: New Delhi
Date: 02.11.2020

ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED
[illegible]

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 at 03:00 PM. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to [illegible]

[illegible]

Place: New Delhi
Date: 02.11.2020

GENESIS DEVELOPERS AND HOLDINGS LIMITED
[illegible]

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the notice is hereby given that, the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 at 03:30 PM at the registered office of the Company to [illegible]

[illegible]

Place: New Delhi
Date: 02.11.2020

HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED
[illegible]

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th November, 2020 at 12:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to [illegible]

[illegible]

Place: New Delhi
Date: 02.11.2020